

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3259
उत्तर देने की तारीख 12.03.2026

वन अधिकार अधिनियम के तहत दावे

† 3259. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदान किए गए वन अधिकार अधिनियम शीर्षकों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वितरित वन भूमि के क्षेत्रफल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने देश में आंकड़े संग्रह के लिए मानदंडों को मानकीकृत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' (संक्षेप में, एफआरए) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं और इन प्रावधानों को 20 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में लागू किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) की निगरानी करता है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान, अर्थात् 01.01.2021 से 01.01.2026 तक, एफआरए के तहत कुल 5,45,802 अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान एफआरए के तहत वितरित अधिकार पत्रों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

रिपोर्टिंग अवधि	एफआरए के तहत वितरित अधिकार पत्रों की संख्या
01.01.2021 से 01.01.2022 तक	79466
01.01.2022 से 01.01.2023 तक	183804
01.01.2023 से 01.01.2024 तक	88126
01.01.2024 से 01.01.2025 तक	146153
01.01.2025 से 01.01.2026 तक	48253
कुल	545802

(ख): राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात् 01.01.2023 से 01.01.2026 तक, एफआरए के तहत कुल 69,19,108.23 एकड़ वन भूमि वितरित की गई थी।

(ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) को संकलित करता है। माह-वार एमपीआर (मासिक प्रगति रिपोर्ट) जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट <https://tribal.nic.in/FRA.aspx> पर उपलब्ध हैं।
